



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1993/बैत 10, 1915

No. 196] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1993/CHAITRA 10, 1915

इस भाग में विस्तृ पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि पहले अंग संकेतन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a  
separate compilation

उद्धारण मन्त्रालय

(आंशिक विकास विभाग)

मुद्रण

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

का प्रा 218(अ) / 18क/ग्राइड डा प्रा.र.प. / 93--मार्ग सरकार के उद्योग मन्त्रालय  
(आंशिक विकास विभाग) के कानून अ. इंग. 52। 157(अ) 18क/ग्राइड डा प्रा.र.प. /  
79, त.राय 27 मार्च, 1979 द्वारा (जि. इसमें उसके पश्चात् उन्नीस देश का दाया है)

कलकत्ता में स्थित मैसर्स विल्ली ब्रिस्कुट कंपनी (ब्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स विल्ली बालौ मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक दोनों औद्योगिक उपकरण के प्रबंध का 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिये अधिग्रहण किया गया था और रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग, जो अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, में पश्चिम बंगाल सरकार के सचिव को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था,

और यह केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीक्षीय है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे 31 मार्च, 1993 तक की और अवधि के लिये ऐसे बने रहने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये थे। देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश-

मं. का.आ. 178(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./82, तारीख 26 मार्च, 1982

मं.का.आ. 688(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./82 तारीख 25 मिस्राचर, 1982

मं.का.आ. 384(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./83, तारीख 31 मई, 1983

मं.का.आ. 936(अ)/19क/प्राई.डी.आर.ए./83, तारीख 29 दिसंबर, 1983

मं.का.आ. 469(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./84, तारीख 28 जून, 1984

मं.का.आ. 967(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./84, तारीख 28 दिसंबर, 1984

मं.का.आ. 280(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./85, तारीख 30 मार्च, 1985

मं. का.आ. 144(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./86, तारीख 31 मार्च, 1986

मं.का.आ. 271(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./87, तारीख 30 मार्च, 1987

मं.का.आ. 327(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./88, तारीख 30 मार्च, 1988

मं.का.आ. 246(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./89, तारीख 31 मार्च, 1989

मं.का.आ. 275(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./90, तारीख 30 मार्च, 1990

मं.का.आ. 213(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./91, तारीख 26 मार्च, 1991 और

मं.का.आ. 249(अ)/18क/प्राई.डी.आर.ए./92, तारीख 30 मार्च, 1992

और यह केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीक्षीय है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1994 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे,

ग्रत., श्रव., केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का धारा 18क के उपशारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि 27 मार्च, 1979 का उक्त आवेदन 31 मार्च, 1994 तक का, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[फा.स. 2(3)/80 सी.यू.एस./आई.आर.एस.]

ग्रबण्ड प्रताप सिंह, मयुक्त सचिव

**MINISTRY OF INDUSTRY**  
**(Department of Industrial Development)**  
**ORDER**

New Delhi, the 31st March, 1993

S.O. 218(E)|18A|IDRA|93.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)|18A|IDRA 79 dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order) the management of industrial undertakings known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta, was appointed as 'Authorised Controller'.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto 31st March, 1993 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development).

Nos S.O. 178(E)|18A|IDRA|82, dated the 26th March, 1982,

S.O. 638(E)|18A|IDRA|82, dated the 25th September, 1982,

S.O. 384(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st May, 1983,

S.O. 936(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th December, 1983,

S.O. 469(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 967(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th December, 1984,

S.O. 280(E)|18A|IDRA|85, dated the 30th March, 1985,

S.O. 144(E)|18A|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,  
S.O. 271(E)|18A|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,  
S.O. 327(E)|18A|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,  
S.O. 246(E)|18A|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,  
S.O. 275(E)|18A|IDRA|90, dated the 30th March, 1990,  
S.O. 213(E)|18A|IDRA|91, dated the 26th March, 1991 and  
S.O. 249(E)|18A|IDRA|92, dated the 30th March, 1992.

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1994.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1994.

[File No. 2(3), 89-CUS (RS)]

A. P. SINGH Jt. Secy.